www.sanjanabharati.com
दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित
facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 मांसाहारी खाने पर जारी 'सेक्युलर सियासी...
3 'रोड रूल्स, लाइफ टूल्स' अभियान के तहत करनाल...
4 वैश्विक लीडर अपूर्व शर्मा ने छात्रों में भरी नई...

वर्ष: 9 | अंक: 271 | दिल्ली, शुक्रवार, 25 जुलाई 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कलाकारों से की मुलाकात

नई दिल्ली (एजेन्सी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को यहां राष्ट्रपति भवन में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कलाकारों के एक समूह से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सोहराय, पट्टचित्र और पटुआ क्षेत्र के ये 29 कलाकार 14 से 24 जुलाई तक राष्ट्रपति भवन में रहे। राष्ट्रपति कार्यालय ने बयान में कहा, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कलाकार राष्ट्रपति भवन के कला उत्सव 2025-आवासीय कलाकार कार्यक्रम के दूसरे संस्करण में भागीदार थे। बयान के मुताबिक यह कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। यह सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने में जीवंत कला परंपराओं की महत्वपूर्ण भूमिका की पुनः पुष्टि है। कला उत्सव ने लोक, जनजातीय और पारंपरिक कलाकारों को भी एक मंच प्रदान किया, जिन्होंने पीढ़ियों से कला के विविध रूपों को जारी रखा है।

गुरुजी यह जंग भी जीतेंगे: हेमंत सोरेन

झारखंड (एजेन्सी)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया कि उनके पिता और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक शिबू सोरेन अपने स्वास्थ्य की जंग भी जीतेंगे, जिस प्रकार उन्होंने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी और जीती हैं। शिबू सोरेन पिछले एक महीने से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी समेत कई प्रमुख नेताओं ने अस्पताल पहुंच कर उनका हालचाल लिया है। सोरेन की बीमारी के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और परिवार के अन्य सदस्य ज्यादातर दिल्ली में ही रह रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता के बाद मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

सीएम रेखा गुप्ता की तीन बड़ी सौगातें: दिल्ली में अब स्वास्थ्य सेवाएं होंगी डिजिटल, सस्ती और सुलभ

संजना भारती/संजय कुमार

नई दिल्ली। दिल्ली की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज तीन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं का डिजिटल शुभारंभ किया। इनमें अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआईएमएस), 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आठ नए जन औषधि केंद्र (जेएके) शामिल हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों का डिजिटलीकरण होना उसकी प्रगति का सूचक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया और कहा कि केंद्र के मिले बजट से हम दिल्ली का हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की राजधानी के लोगों को अब इतना विकसित स्वास्थ्य सिस्टम मिलेगा कि उन्हें अपना इलाज करवाने में कोई तकलीफ नहीं होगी।

विकसित स्वास्थ्य सिस्टम से दिल्ली वालों का होगा आसानी से इलाज: गुप्ता

दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह, कई विधायक, मुख्य सचिव धर्मेंद्र व स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराया कि उनकी सरकार एक सशक्त, समावेशी और तकनीक-सक्षम स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिससे दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत करने में

लगी है। एक महीना पहले 33 आयुष्मान केंद्रों का उद्घाटन हुआ। आज फिर हम 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके बाद विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में इन्हें जनता को समर्पित करने का कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है। हमारी सरकार ने 93 लाख आभा आईडी यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडीज क्रिएट किए हैं। अब दिल्ली के हर निवासी का डिजिटल हेल्थ कार्ड सरकार के पास होगा। ताकि उसी के आधार पर कहीं भी और किसी भी अस्पताल में वह अपना इलाज करवा सकता है। यह दिल्ली सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी जानकारी दी कि इसी तरह से अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचआईएमएस) भी शुरू कर दी गई है। अब अगर किसी व्यक्ति को ओपीडी, टेस्टिंग के लिए टाइम लेना है, अस्पताल से जुड़े लैब, रेडियोलोजी, मेडिकल रिकॉर्ड, बिलिंग, एंबुलेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, हर तरह की प्रक्रिया की जानकारी लेनी है तो इस डिजिटल प्लेटफार्म पर जाकर अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं। अब मरीज या उसका रिश्तेदार घर बैठे अपने लिए डॉक्टर से टाइम तय करवा लेगा। उसे कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार दिल्ली की जनता का हेल्थ रिकॉर्ड बना रही है। लोग अपना कार्ड प्रस्तुत करेंगे, उसकी जांच के बाद इलाज शुरू हो जाएगा।

इस तरह से राजधानी के अस्पतालों का डिजिटलीकरण होना दिल्ली की प्रगति का सूचक है।

अश्विनी वैष्णव ने पत्र लिखकर दी जानकारी, पटना से चलाई गई हैं 17 नई ट्रेनें

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

गोरखपुर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद गिरधारी यादव को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बिहार के रेलवे नेटवर्क का अभूतपूर्व विकास हुआ है। वर्ष 2014 के बाद यहां लगभग 1,900 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण हुआ। 2025-26 में राज्य को रिकॉर्ड 10,066 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया।

बिहार में 13 वंदे भारत एक्सप्रेस, 5 अमृत भारत एक्सप्रेस और एक नमो भारत रैपिड रेल का परिचालन प्रारंभ किया गया है। साथ ही मोदी जी की सरकार ने 2014 के बाद पटना से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए 17 ट्रेनें चलाई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गिरधारी यादव को लिखे गए पत्र में उन ट्रेनों की सूची की संलग्न की है, जिनका परिचालन पटना से होता है। इन ट्रेनों में शामिल हैं।

1. सहरसा-आनंद विहार एक्सप्रेस (15529/15530)
2. मालदा टाउन-आनंद विहार एक्सप्रेस (13429/13430)
3. पटना-बैंगलोर प्रीमियम एक्सप्रेस (22353/22354)
4. जयनगर-लोकमान्य तिलक जनसाधारण एक्सप्रेस (15547/15548)
5. नाहरलगुन-नई दिल्ली एक्सप्रेस (22411/22412)
6. पटना-मुंबई सीएसटीएम सुविधा एसी एक्सप्रेस (22355/22356)
7. अगरतला-आनंद विहार एक्सप्रेस (14019/14020)
8. पटना-बांद्रा टर्मिनस हमसफर एक्सप्रेस (22913/22914)
9. अगरतला-आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस (20501/20502)
10. मधुपुर-आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस (12235/12236)
11. पटना-बनासवाड़ी हमसफर एक्सप्रेस (22353/22354)
12. आनंद विहार-मधुपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (22465/22466)
13. आनंद विहार-मधुपुर हमसफर एक्सप्रेस (22459/22460)
14. गोड्डा-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस (22311/22312)
15. लोकमान्य तिलक-सहरसा अमृत भारत एक्सप्रेस (11015/11016)
16. राजेंद्र नगर-नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस (22361/22362)
17. बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस (15567/15568)

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए खोला घोषणाओं का पिटारा

मकानों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन तारों को 3 करोड़ रुपये के सरकारी खर्च पर हटाया जाएगा

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए कहा कि बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र में मकानों के ऊपर से गुजर रही हाइटेंशन तारों को बिजली विभाग द्वारा हटवाया जाएगा और इसके लिए 3 करोड़ रुपये की राशि बिजली विभाग को दी जाएगी। ये सारा खर्च सरकार वहन करेगी। इसके अलावा, बाढड़ा में भूमि उपलब्धक होने पर नई अनाज मंडी स्थापित करने, गावं हड़ौदा में फिजिबिल्टी चैक करवाकर सब्जी मंडी का निर्माण करने तथा गांव झोंझूकलां को महाग्राम योजना में शामिल करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं वीरवार को जिला चरखी दादरी के बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र के झोझूकलां में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए की। इस मौके पर सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि बाढड़ा विधानसभा में कुछ गांवों की चकबंदी बकाया है, उन गांवों की चकबंदी का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, गांव पातुवास में भूमि उपलब्ध होने पर पशु चिकित्सालय

बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़डा को बिजली का डिविजन का दर्जा दिया जाएगा और बिजली कार्यालय का निर्माण करवाया जाएगा, इसके लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपये की घोषणा की। साथ ही, फिजिबिल्टी चैक करवाकर बाढड़ा पब्लिक हेल्थ की सब डिविजन को डिवीजन का दर्जा दिलवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कलियाना से दादरी सड़क को चार-लेन करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसकी फिजिबिलिटी चैक करवाकर इस कार्य को किया जाएगा। झोझूकलां को उप तहसील का दर्जा देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में सरकार द्वारा गठित कमेटी को आवेदन किया जाए। इसके अलावा, फिजिबिलिटी चैक करवाकर बाढड़ा में फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। महराणा एवं ढाणी फौगाट में सरकारी स्कूलों को बारहवीं तक अपग्रेड करने के संबंध में फिजिबिलिटी चैक करवाकर इनको अपग्रेड करने का काम किया जाएगा।

श्री नायब सिंह सैनी ने सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए घोषणा करते हुए कहा कि बाढ़डा विधानसभा में 311.20 किलोमीटर की 100 सड़कें, जो डीएलपी अवधि में हैं, उन्हें संबंधित एजेंसी के माध्यम से ठीक करवाया जाएगा। इसके अलावा, पीडब्ल्यूडी की 48.31 किलोमीटर की 12 सड़कों की मरम्मत के लिए 20.40 करोड़ रुपये की घोषणा की। बाढ़डा क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड की 13.80 किलोमीटर की पांच सड़कों की भी स्पेशल रिपेयर करवाई जाएगी। साथ ही, 11.70 किलोमीटर की 3 सड़कों की स्पेशल रिपेयर के लिए 1.19 करोड़ रुपये की घोषणा की। इसके अलावा, इस क्षेत्र में 63.9 किलोमीटर की 21 सड़कें, जो डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि में हैं, उनकी भी संबंधित एजेंसी के माध्यम से मरम्मत करवाई जाएगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि कारी-रूपा में फिजिबिलिटी चैक करवाकर यहां आईटीआई खोलने का काम किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने बाढ़डा विधानसभा में गांवों के कच्चे रास्तोंए का निर्माण करने के लिए 5 करोड़ रुपये तथा इस विधानसभा क्षेत्र के गांवों के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

चुनौतियों से लड़कर नीट में सफल होने वाले श्रवण कुमार का राज्यपाल ने सम्मान किया

जयपुर/एसबी संवाददाता। बालोतरा जिले के छोटे से गांव से आने वाले श्रवण कुमार द्वारा नीट परीक्षा 2025 क्लियर करने को महत्वपूर्ण बताते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बालोतरा में उनको सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि श्रवण कुमार की कामयाबी सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि गरीबी और संघर्ष के बावजूद हासिल की गई एक असाधारण जीत है। राज्यपाल ने इसकी सराहना करते हुए दूसरों के लिए इसे अनुकरणीय बताया। राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में श्रवण कुमार को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि श्रवण और उसके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाए और उन्हें पात्रतानुसार जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाए।

देश को 23 साल बाद मिली नई सहकारिता नीति-अमित शाह

नई दिल्ली (एजेन्सी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का अनावरण किया, जो पिछले 23 वर्षों से लागू एक नीति का स्थान लेगी। यह उस विभाग के लिए एक और मील का पत्थर साबित होगी जिसकी भूमिका नरेंद्र मोदी सरकार के तहत लगातार बढ़ रही है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, नई नीति देश में सहकारिता को मजबूत करने के केंद्र के उद्देश्य का हिस्सा है और 2025-45 तक यानी अगले दो दशकों के लिए भारत के सहकारिता आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगी। अमित शाह ने कहा कि आज राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 का शुभारंभ हुआ है। 2002 में, भारत सरकार ने सहकारिता नीति पेश की थी। उस समय भाजपा की सरकार थी। और आज, 2025 में, भाजपा सरकार द्वारा दूसरी सहकारिता नीति लाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण, जो भारत को, उसके विकास को, और भारत के विकास के लिए आवश्यक सभी कारकों को समझता है, वही सहकारी क्षेत्र को महत्व दे सकता है...यदि देश और अर्थव्यवस्था की मूल इकाई समृद्ध, रोजगारयुक्त और संतुष्ट है, तो वह आर्थिक मॉडल कभी विफल नहीं हो सकता।

उपमुख्यमंत्री ने किया जैसलमेर स्थित वॉर म्यूजियम का अवलोकन

एसबी संवाददाता

जयपुर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने गुरुवार को अपने जैसलमेर प्रवास के दौरान परिवार सहित जैसलमेर स्थित वॉर म्यूजियम का अवलोकन किया। उन्होंने वहां वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके बलिदान को नमन किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वॉर म्यूजियम केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि यह मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले रणबांकुरों की अमर गाथाओं का जीवंत प्रतीक है। यहां आकर देशभक्ति, शौर्य, बलिदान और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अद्भुत अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि युद्ध इतिहास में दर्शाए गए वीरता के किस्से आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यह स्थल हमें यह याद दिलाता है कि हमारे सैनिकों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और उनका यह बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने वॉर म्यूजियम में प्रदर्शित युद्ध सामग्री, चित्रों एवं ऐतिहासिक तथ्यों का भी अवलोकन किया और उसे अत्यंत प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के स्मारक युवाओं को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते हैं।

इस दौरान जिला प्रशासन एवं सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा वॉर म्यूजियम की विशेषताओं की जानकारी दी।

साल 2025 के सिर्फ 6 महीनों में दिल्ली में 118 साफ वायु गुणवत्ता वाले दिन दर्ज, 2016 के पूरे साल के 110 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा: सिरसा

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। 1 जनवरी से 24 जुलाई 2025 तक दिल्ली में 118 ऐसे दिन दर्ज किए गए हैं जब वायु गुणवत्ता साफ श्रेणी में रही। यह संख्या 2016 में पूरे साल में दर्ज 110 दिनों को पार कर गई है। यह रुझान दर्शाता है कि 2025 के अंत तक पिछले एक दशक में दिल्ली पहले के मुकाबले दोगुनी संख्या में स्वच्छ वायु वाले दिन हासिल कर सकती है।

पर्यावरण हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (अदक) 91 रहा, जो सैटिसफैक्टरी श्रेणी में आता है। 24 जुलाई को पंजाबी बाग (64), बवाना (71) और नरेला (77) शहर के सबसे साफ हॉटस्पॉट्स रहे। पर्यावरण मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस लगातार हो रही प्रगति का श्रेय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में शुरू की गई बहुस्तरीय और जमीनी गतिविधियों पर केंद्रित रणनीति को दिया। उन्होंने कहा, हम रुकने की स्थिति में नहीं हैं। हमारी टीमें रोजाना जमीन पर मौजूद हैं। हमारा लक्ष्य केवल प्रदूषण को घटाना नहीं, बल्कि उसे लगातार नीचे बनाए रखना है। श्री सिरसा ने कहा, ये 118 स्वच्छ

वायु वाले दिन संयोग नहीं हैं। यह विभिन्न एजेंसियों के समन्वय, त्वरित प्रवर्तन और जनता की भागीदारी का नतीजा है। हम हर वार्ड, हर जोन में हर दिन काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की यह पर्यावरणीय प्रगति विकसित भारत, विकसित दिल्ली मिशन का हिस्सा है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह सहभागी शासन का उदाहरण है जो विज़िबल प्रभाव दिखा रहा है। साल

'गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइट्स से 1,268 मीट्रिक टन पुराना कचरा हटाया गया'

2016 के इसी जनवरी-जुलाई कालखंड में दिल्ली में केवल 45 स्वच्छ वायु वाले दिन दर्ज किए गए थे, जबकि वर्तमान वर्ष में यह आंकड़ा 118 तक पहुँच चुका है- यानी 160% से अधिक की बढ़ोत्तरी।

डेटा यह भी दर्शाता है कि खराब श्रेणी के दिनों की संख्या में भी बड़ी गिरावट आई है। जुलाई 2025 को एक दशक का सबसे स्वच्छ जुलाई माना जा रहा है।

श्री सिरसा ने स्पष्ट किया कि यह सुधार किसी एक क्षेत्र या मौसम तक सीमित नहीं है: हमने जवाबदेही को विकेंद्रित किया है और जमीनी टीमों को त्वरित कार्रवाई के लिए सक्षम किया है। चाहे स्थानीय कूड़े का ढेर हो, धूल फैलाने वाली साइट हो या कोई वाहन प्रदूषण हॉटस्पॉट-इंफोर्समेंट अब रीयल टाइम में हो रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किया मतदान

एसबी संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के क्रम में गुरुवार को राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय नगला तराई, जिला ऊधमसिंह नगर में बूथ न0 3 पर लाईन में लगकर मतदान किया। मुख्यमंत्री के साथ उनकी माताजी श्रीमती बिशना देवी ने भी मतदान किया। मुख्यमंत्री ने सभी ग्रामीण मतदाताओं से त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में उत्साह पूर्वक मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता का एकएक वोट राज्य में पंचायतों को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

तेलंगाना में जाति जनगणना को लेकर गदगद हुए राहुल

(एजेन्सी)।

तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की और राज्य में जाति सर्वेक्षण के प्रमुख विवरणों पर चर्चा की। दूसरी ओर एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर काम किया। उन्होंने न केवल जाति जनगणना उस भावना से की जिस भावना से होनी चाहिए थी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस कुशलता से उन्होंने इसे किया है, वह देश में सामाजिक न्याय के लिए एक मील का पत्थर है। यह तय करेगा कि राष्ट्रीय जाति जनगणना कैसी होगी, चाहे भाजपा इसे पसंद करे या न करे। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह एक सामाजिक औजार है और साथ ही एक वित्तीय, आर्थिक औजार भी है। भाजपा को यह पसंद नहीं है कि यह एक राजनीतिक औजार भी है।

सम्पादकीय

डिजिटल युग

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि तकनीक मात्र उपकरण बनें तो यह मानवता के हित में नहीं हो सकती। ऐसे में तकनीक को जनकल्याण का माध्यम बनाना होगा। डिजिटल युग में बहुत कुछ बदला है। हमारे सोच का तरीका बदला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आज सामान्य मानव मन से भी अधिक तेजी से तकनीक काम करने लगी है। तकनीक ने इतना विकास कर लिया है कि अब मशीनें सोचने लगी है। हमारे चिंतन और मनन को प्रभावित करने लगी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि तकनीक ने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रवेश करने के साथ सहज बनाया है। समय तो यहां तक बदल गया है कि अब पढ़ना-लिखना ही नहीं तकनीक ने सोचना और निकश तक पहुंचना आरंभ कर दिया है। यह विकास का उजला पक्ष होने के साथ ही इसके पीछे छुपा काला पक्ष भी गंभीर है। हालांकि प्रकृति अपना काम कर रही है और वह लगातार हमें चेतावनी देती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। वह हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रही है, हमारी प्राथमिकताएं तय कर रही है, और हमारी सोच को प्रभावित कर रही है। इस दौर में हमें ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो तकनीक के चमत्कारों को संवेदनशीलता और दूरदृष्टि के साथ दिशा दे। एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सटीक और सामयिक टिप्पणी की है। दरअसल ह्यूटेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। हमें जन-केंद्रित एप्लिकेशन बनाने चाहिए। साथ ही हमें साइबर सुरक्षा, दुष्प्रचार और डीपफेक जैसी चुनौतियों का समाधान भी करना होगा। डिजिटल नवाचार का उपयोग अब पारदर्शिता, सहभागिता और संवेदनशील सेवा-प्रणाली के रूप में सामने आ रहा है। हमारा देश आज एआई और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रख रहा है। 2024 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित इंडिया एआई मिशन इसका जीता जागता उदाहरण है। इस मिशन के तहत 10,300 करोड़ रु. के निवेश से देश में एक विश्वस्तरीय एआई कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है 18,693 जीपीयू से लैस साझा कंप्यूटिंग क्षमता विकसित कर भारत को वैश्विक एआई शक्तियों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिस्टम ओपन-सोर्स एआई मॉडल डीपसीक से 9 गुना अधिक सक्षम होगा और चैटजीपीटी जैसी प्रणालियों की दो-तिहाई शक्ति तक पहुंचेगा। यानी यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं होगी अपितु डिजिटल क्षेत्र में भारत को आत्मसम्मान व दुनिया के देशों की अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने की घोषणा है। दरअसल तकनीक का उपयोग मानव कल्याण के उद्देश्य से होना चाहिए। सरकारें इस बात को समझती है और यही कारण है कि ई-गवर्नेंस से लेकर डिजिटल शिक्षा, एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं और नागरिक सुविधा केंद्रों तक हर नीति के केंद्र में आम आदमी है, सिस्टम नहीं। राज्यों में तकनीक को डिजिटल एक्सेस के बजाय डिजिटल एम्पावरमेंट के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। और यही बदलाव राज्यों को एक सॉफ्ट-टेक्नोलॉजिकल स्टेट बना रहा है। राज्यों में चल रहे हरित अभियान, जल संरक्षण योजनाएं, सौर ऊर्जा प्रोत्साहन और ईको-टूरिज्म और इसी तरह की अन्य पहल इस सोच के साथ धरातल पर उतर रही हैं। यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य अभियान, डिजिटल डिटॉक्स क्लासेस और संस्कार संवाद जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ताकि युवा स्मार्टफोन के स्क्रीन से आगे सोच सकें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। आज सवाल यह नहीं कि हमें तकनीक से डरना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि हम तकनीक को किस नैतिक दायरे में संचालित कर सकते हैं। केन्द्र के साथ ही राज्यों की सरकारें इसे समझने लगी है और यह कारण है कि राज्यों द्वारा तकनीक का उपयोग भविष्य की संभावनाओं और जनकल्याण नीतियों के रुप में सामने आ रहा है।

जयंती

सोमनाथ चटर्जी

जन्म: 25 जुलाई, 1929, तेजपुर, असम; मृत्यु: 13 अगस्त, 2018, पश्चिम बंगाल) 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी' के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे चौदहवीं लोकसभा में पश्चिम बंगाल के बोलपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। श्री चटर्जी चौदहवीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष भी थे। विगत वर्षों में भारतीय संसद के कई प्रमुख अध्यक्ष हुए हैं, जिन्होंने अध्यक्षपीठ को गरिमा और सम्मान प्रदान किया है। सोमनाथ चटर्जी 4 जून, 2004 को इस सम्माननीय पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित होकर अध्यक्षों के दीप्ति मंडल में सम्मिलित हुए। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि-'अध्यक्ष राष्ट्र, उसकी स्वतंत्रता और आजादी का प्रतिनिधित्व करता है।'

पुण्यतिथि

गोदावरीश मिश्र

जन्म-26 अक्टूबर, 1886, पुरी, उड़ीसा; मृत्यु-25 जुलाई, 1956) उड़ीसा के प्रसिद्ध समाज सुधारक, साहित्यकार और सार्वजनिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने कविता, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ तथा जीवन चरित्र आदि लिखे हैं। 'भारतीय साहित्य अकादमी' ने उनकी आत्मकथा को पुरस्कृत किया था। गोदावरीश मिश्र जी ने 1941 में उड़ीशा के शिक्षामंत्री और वित्तमंत्री का पद भी सम्भाला था।

कल मिलेंगे

पत्नी: सुनो जी, आज मैंने एक सपना देखा।
पति: क्या?
पत्नी: मैंने देखा कि तुम मुझे 1000 गुलाब के फूल दे रहे हो।
पति: (खुशी से) वाओ! तो क्या तुम मुझे कोई खास गिफ्ट दोगी?
पत्नी: हाँ, मैं तुम्हें एक गुलाब का पौधा दूंगी।

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

मांसाहारी खाने पर जारी 'सेक्युलर सियासी खेल' के साइड इफेक्ट्स को ऐसे समझिए

-कमलेश पांडेय

आमतौर पर यह माना जाता है कि इस्लामिक शासनकाल में और ब्रिटिश शासनकाल में सनातन भूमि पर गुरुकुल, ब्रह्मचर्य व शाकाहार को हतोत्साहित किया गया और मांसाहार तथा मद्यपान को प्रोत्साहित किया गया। जिससे कई सामाजिक कुरूतियों जैसे कोठा संस्कृति वाली वैश्यावृत्ति और अनैतिक अपराध को बढ़ावा मिला। ऐसा इसलिए कि दूषित अन्न खाने व दूषित पेय-पदार्थ पीने से मानवीय मनोवृत्ति विकृत हुई

सनातनी हिंदुओं के पवित्र श्रावण यानी सावन के महीने में या आश्विन माह में पड़ने वाले शारदीय नवरात्र के दिनों में पिछले कुछ वर्षों से नॉन-वेज फूड को लेकर जो विवाद सामने आ रहे हैं, वह इस बार भी प्रकट हुए और पक्ष-विपक्ष की क्षुद्र राजनीति के बीच अपनी नीतिगत महत्ता खो बैठे। वहीं, तथाकथित एनडीए शासित राज्य की बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में गत सोमवार को खाने में जिस तरह से नॉन-वेज भी परोसा गया, उसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं।

इसी तरह, यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग स्थित ढाबों और भोजनालयों पर दुकान मालिकों की पहचान स्पष्ट करने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में उठा। स्पष्ट है कि यहां भी मूल में भोजन ही है। इसलिए पुनः यह सवाल अप्रासंगिक है कि कोई क्या खाता है, क्या नहीं, यह पूरी तरह व्यक्तिगत मामला है और इस पर ऐसे विवाद से बचा जा सकता था। लेकिन ऐसे सो कॉल्ड सेक्यूलर्स और वेस्टर्न लॉ एडवोकेट्स को पता होना चाहिए कि सदियों से भारतीय समाज एक संवेदनशील व सुसंस्कृत समाज रहा है, जहां स्पष्ट मान्यता है कि खान-पान से व्यक्ति के मन का सीधा सम्बन्ध होता है।

कहा भी गया है कि जैसा खाए अन्न, वैसा बने मन। इसलिए राजा या शासक का कर्तव्य है कि वह आमलोगों को शुद्ध और सुरुचिपूर्ण भोजन ग्रहण करने योग्य कानून बनाए और उसकी सतत निगरानी रखे। चूंकि भारतीय समाज में शाकाहारी खानपान को प्रधानता दी गई है ताकि निरोगी जीवन का आनंद लिया जा सके। इसलिए ऐसे लोगों को अभक्ष्य पदार्थों यानी अंडे, मांस-मछली का दुर्गंध नहीं मिले, इसकी भी निगरानी रखना प्रशासन का काम है। वहीं, खान-पान के व्यवसाय से जुड़ी कम्पनियां शाकाहारी लोगों को मांसाहारी उत्पाद डिलीवर न कर दें, मिलावटी शाकाहारी समान न डिलीवरी कर दें, यह देखना भी प्रशासन का ही धर्म है। यदि वह धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अपने नैतिक दायित्वों से मुंह मोडता है तो उसे भारत पर शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए देश की भाजपा नीत एनडीए सरकार, या विभिन्न राज्यों की भाजपा सरकारें या एनडीए सरकारें इस बात की कोशिश कर रही हैं कि खास पर्व-त्यौहारों पर निरामिष लोगों के अनुकूल माहौल बनाए रखा जाए।

आमतौर पर यह माना जाता है कि इस्लामिक शासनकाल में और ब्रिटिश शासनकाल में सनातन भूमि पर गुरुकुल, ब्रह्मचर्य व शाकाहार को हतोत्साहित किया गया और मांसाहार तथा मद्यपान को प्रोत्साहित किया गया। जिससे कई सामाजिक कुरूतियों जैसे कोठा संस्कृति वाली वैश्यावृत्ति और अनैतिक अपराध को बढ़ावा मिला। ऐसा इसलिए कि दूषित अन्न खाने व दूषित पेय-पदार्थ पीने से मानवीय मनोवृत्ति विकृत हुई।

इसलिए कहा जा सकता है कि उदार और सहनशील भारतीय समाज का जो नैतिक पतन हुआ है, कभी-कभी स्थिति पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों के काबू से बाहर हो जाती है, उसका सीधा सम्बन्ध असामाजिक तत्वों के खानपान से भी है। इसलिए इस अहम मुद्दे के सभी पहलुओं पर निष्पक्षता पूर्वक विचार होना चाहिए। इस मामले में आधुनिक प्रशासन का ट्रैक रिकार्ड बेहद ही खराब रहा है, अन्यथा जानलेवा मिलावट खोरी इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती। मीडिया रिपोर्ट्स भी इसी बात की चुगली करती आई हैं। जहां तक व्यक्तिगत चुनाव की बात है तो यह अपने घर पर ही लागू हो सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पर बिल्कुल नही। इस बात में कोई दो राय नहीं कि खाने-पीने की पसंद किसी व्यक्ति की पहचान और उसकी संस्कृति का हिस्सा होती है। इसलिए भारत में जैसी विविधता पूर्ण संस्कृति रहती आई है, वैसे ही यहां के खाने में भी विविधता सर्वस्वीकार्य है। इसलिए किसी को क्या खाना चाहिए, इसकी पुलिसिंग होनी चाहिए या नहीं, विवाद का विषय है।

कहना न होगा कि जैसे कानून किसी को भी जहर खाने की इजाजत नहीं देता है, वैसे ही मीठे जहर के रूप में प्रचलित बाजारू चीजों की भी जांच-पड़ताल की जानी चाहिए और यदि वे जनस्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल हों तो उनपे निर्विवाद रूप से रोक भी लगनी चाहिए। यही बात मांसाहार पर भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि इससे मानवीय शरीर में विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगाणुओं को भी बढ़ावा मिलता है। बर्ड फ्लू इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

कुछ लोग बताते हैं कि लोगों के खानपान की पुलिसिया निगरानी या ऐसी कोई भी कोशिश संविधान के उस अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगी, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। इसलिए भोजन और पहनावा भी इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। लेकिन यह सिर्फ घर के चहारदीवारी के भीतर होनी चाहिए, वो भी तभी तक जब तक कि पड़ोसी को आपत्ति नहीं हो।

ऐसा इसलिए कि आधुनिक फ्लैट संस्कृति में एक घर के रसोई की सुगंध या दुर्गंध पड़ोसियों के बेडरूम तक पहुंच जाती हैं। इसलिए भोजन निजी पसंद की चीज है, लेकिन बगलगीर की भावनाओं का सम्मान करना भी मांसाहारियों की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि कुछ शाकाहारी लोग तो दुर्गंध मात्र से उल्टी कर बैठते हैं। इससे उनका जीवन भी खतरे में आ जाता है।

इसलिए यह राजनीतिक विवाद का विषय नहीं, बल्कि सियासी सूझबूझ का परिचायक समझा जा सकता है। भारतीय राजनीति की एक सबसे बड़ी कमी यह महसूस की जाती है कि हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को जनहितैषी बनाने में यह विगत सात-आठ दशकों में भी शत-प्रतिशत क्या, पचास प्रतिशत भी सफल नहीं हुई है। लोकतंत्र और पाश्चात्य लोकतांत्रिक मूल्यों, जिस खुद पश्चिमी देश अपनी सुविधा के अनुसार चलते हैं, भारत में आँखमूद कर लागू कर दिए जाते हैं। इसलिए व्यापक जनहित का सवाल व्यवहारिक रूप से काफी पीछे छूट जाता है।

हालांकि इसके बाद भी सावन में पिछले कुछ वर्षों से नॉन-वेज फूड को लेकर विवाद खड़े होते रहे हैं। देखा जाए तो ज्यादातर के मूल में राजनीति होती है। बिहार में दो साल पहले भी सावन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी के घर जाकर मटन पकाना एक सियासी मुद्दा बन गया था। कुछ दिनों पहले, जब प्रशांत किशोर की पार्टी में बिरयानी बंटी, तब भी हंगामा हुआ और सफाई देनी पड़ी कि यह तो वेज थी! यही वजह है कि खानपान को लेकर नीतिगत संतुलन की जरूरत सबको है। इसलिए आस्था को भोजन के साथ मिलाने पर जो समस्या खड़ी होती है, वैसी ही समस्या इसकी अनदेखी के पश्चात भी खड़ी होती बताई जाती है। चूंकि दोनों ही निजी मामले हैं और दोनों में ही किसी को दखल देने का हक नहीं है। हां, यह जरूर है कि जब बात किसी खास आयोजन या धार्मिक अवसर पर किसी समुदाय की भावनाओं से जुड़ी हो, तो वहां सभी पक्षों के संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही होता भी आया है। वहीं, भोजन किसी व्यक्ति की गरिमा का सवाल भी है। असल में, भोजन केवल भूख से नहीं, व्यक्ति की गरिमा से भी जुड़ा होता है। यह सम्मान के साथ कमाने और खाने का हक इस देश के सभी नागरिकों को देता है। किसी भी वजह से इन हकों को छीनने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। फिर यह भी देखना चाहिए कि खाने का इस्तेमाल राजनीति की बिसात पर न हो। साथ ही, इस राजनीति से लोगों की रोजी-रोटी पर आंच भी नहीं आनी चाहिए।

आखिर हमें यह मानना पड़ेगा कि भजन की तरह भोजन भी स्वरूचि का विषय है। लेकिन जिस तरह से भजन का नाता आतंकवाद और विघटन कारी तत्वों से जुड़ गया है, कुछ वैसी ही आशंका भोजन को लेकर भी जन्म ले रही हैं। इसलिए विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और मीडिया के स्वविवेक से जब इस जटिल मुद्दे का समाधान भारतीय सभ्यता-संस्कृति के अनुरूप निकाला जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि शाकाहारी लोगों की जनभावना आहत नहीं होंगी।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस किस-किस की पैरवी करेगी

-योगेंद्र योगी

अपने जीजाजी की पैरवी करने से पहले राहुल गांधी शायद यह भूल गए कि सोनिया गांधी और खुद उन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामले चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुआ था। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 हैं

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुरूआती चार्जशीट दायर करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर वाड्रा को जानबूझ कर परेशान करने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार के मामलों में कांग्रेस की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि राहुल के इस आरोप के चंद दिनों बाद ही ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने भूपेश बघेल के आवास सहित कई स्थानों पर छापेमारी की और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। यह घोटाला 2019-2022 के दौरान लगभग 2161 करोड़ रुपए की अवैध वसूली से जुड़ा है। सवाल यह है कि राहुल, सोनिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे आखिरकार किस-किस कांग्रेस के नेता के भ्रष्टाचार के लिए केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को दुर्भावना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे।

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुरूआती चार्जशीट दायर की। इस मामले में ईडी की तरफ से 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले पर लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे जीजाजी को पिछले 10 सालों से इस सरकार की तरफ से परेशान किया जा रहा है। यह आरोपपत्र है, उसी षडयंत्र का ही एक और हिस्सा हैं। रॉबर्ड वाड्रा के खिलाफ ये चार्जशीट शिखोपुर लैंड डील मामले में पेश की गई है। ईडी के मुताबिक वाड्रा ने यहां 3.53 एकड़ महज 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी, जिसे कुछ ही समय बाद वाड्रा ने 58 करोड़ रुपये में बेच दिया था।

अपने जीजाजी की पैरवी करने से पहले राहुल गांधी शायद यह भूल गए कि सोनिया गांधी और खुद उन पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामले चल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुआ था। ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 हैं। आरोप पत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। राहुल गांधी को वाड्रा के मामले में साजिश नजर आती है। लेकिन दूसरे घोटालों के मामलों में कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामलों में की चुप्पी साबित करती है कि कांग्रेस अपने अतीत को दोहरा रही है।

केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं हैं, लेकिन जिन गिने-चुने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां से भ्रष्टाचार की सूचनाएं आती रहती हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलार-चिक्काबल्लापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (कोमूल) की 2023 भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संबंध में कर्नाटक कांग्रेस विधायक केवाई नानजेगौड़ा की 1.32 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कोलार जिले के मालूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नानजेगौड़ा, कोमुल के अध्यक्ष भी हैं। ईडी के अनुसार कोमुल द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया में एक लिखित परीक्षा और एक साक्षात्कार शामिल था, लेकिन पैसे और राजनीतिक सिफारिशों के बदले में इसमें हेरफेर किया गया था। संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि नांजेगौड़ा की अध्यक्षता वाली भर्ती समिति ने कोमूल के प्रबंध निदेशक के.एन. गोपाल मूर्ति के साथ मिलकर अन्य निदेशकों के साथ मिलकर कुछ कम योग्य उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया, जबकि योग्य उम्मीदवारों को वंचित रखा।

कांग्रेस की हालत यह हो गई कि वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे और पूर्व अध्यक्ष तक भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में रहे हैं। कर्नाटक में खडगे के बेटे राहुल खडगे के नेतृत्व वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को आवंटिक एक जमीन में हेरफेर का आरोप लगाया गया था। कर्नाटक में यदि भाजपा की सरकार होती तो खडगे के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हो जाता। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने संदिग्ध परिस्थितियों में खडगे के परिवार द्वारा संचालित सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन आवंटित थी। दिलचस्प बात यह है कि 5 एकड़ जमीन (खडगे परिवार द्वारा चलाए जा रहे ट्रस्ट को) इलाके में अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के लिए नियम तैयार करने के कुछ दिनों भीतर दी गई थी। इस मामले का खुलासा होने के बाद खडगे बैकफुट पर आ गए थे। खडगे परिवार के स्वामित्व वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ने विवादास्पद स्थल को वापस करके भ्रष्टाचार से मुक्त होने का प्रयास किया।

कांग्रेस जिन भी राज्यों में सत्ता में रही है, उनमें से ऐसा एक भी राज्य नहीं जिनमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार-घोटालों के आरोप नहीं लगे हों। भ्रष्टाचार के मामलों को देखें तो दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के बड़े कांग्रेस नेता सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसी एजेंसियों के निशाने पर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अपने नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार करती है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी की मोदी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है।

सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस में गांधी परिवार खडगे सहित अन्य नेता भाजपा पर दुर्भावना से कार्रवाई का आरोप लगाते रहे हैं, किन्तु अदालतों में चल रहे इनके खिलाफ मामलों में यह दुर्भावना अभी तक साबित नहीं कर सके। चर्चित घोटालों और घपलों में अदालतों से किसी को क्लीन चिट नहीं मिल सकी। सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस का दामन इतना ही पाक साफ है तो ईडी और अन्य एजेंसियों के आरोपों को अदालतों से मुक्ति क्यों नहीं मिल सकी। कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार कर दिया था।

शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि नेताओं को विशेष इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। नेताओं के भी आम नागरिकों जैसे अधिकार हैं। अगर सामान्य गाइडलाइन जारी की तो ये खतरनाक प्रस्ताव होगा। नेताओं की गिरफ्तारी पर अलग से गाइडलाइन नहीं हो सकती। इस टिप्पणी के बाद यह याचिका वापस ले ली गई। निरन्तर भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रही कांग्रेस और विपक्षी दलों को यह बात शायद अभी तक समझ नहीं आई कि जब तक भ्रष्टाचार पर जीरा टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाएंगे, तब तक देश के मतदाताओं से खोया हुआ विश्वास फिर से हासिल नहीं कर पाएंगे।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

हमास ने नेतन्याहू को चिढ़ाया, इजरायली टैकों के उड़ गए चिथड़े

(एजेन्सी)।

गाजा में एक बार फिर हालात बेकाबू हो गए हैं। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर हमले और तेज कर दिए हैं। अल कस्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी कर इजरायली टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। खबर तो ये है कि जबालिया के पास टकराव और भी विकराल रूप ले चुका है। गाजा की छोटी-छोटी गलियों में फिर बमों की आवाज गूंज रही हैं और युद्ध की आंच लगातार भड़क रही है। इजरायली सेना को निशाना बनाने का ताजा वीडियो सामने आया है। जिसे लेकर अल कस्साम ब्रिगेड जो हमास की ही सशस्त्र ईकाई है उसने दावा किया है कि उसने इजरायली टैंकों को खदानों, शार्ट रेंट मिसाइलों से निशाना बनाया है। खबर है कि हमास ने एक इमारत पर हमला भी किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां इजरायली सैनिक मौजूद था।

अल-कस्साम ब्रिगेड ने एक वीडियो फुटेज जारी किया जिसमें उसके लड़ाके जबालिया कैंप में इजराइली सैन्य वाहनों को नजदीक से निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। अल जजीरा द्वारा प्रसारित इस वीडियो में कई ऑपरेशन दिखाए गए, जिनमें एक मर्कवा टैंक को यासीन 105 मिसाइल से नष्ट करना और एक टैंक के अंदर शवाथ विस्फोटक उपकरण का विस्फोट शामिल है। इस फुटेज में इजराइली वाहनों के रास्तों पर निगरानी और विस्फोटक उपकरण लगाना, एक डी9 बुलडोजर को निशाना बनाना और एक बख्तरबंद कार्मिक वाहक पर यासीन 105 मिसाइल से हमला करना भी दिखाया गया है। एक दृश्य में एक घर पर 107 रॉकेट से हमला करते हुए दिखाया गया है जहाँ इजराइली सैनिक छिपे हुए थे।

एक और बड़ा प्लेन हादसा, 50 यात्रियों को लेकर उड़ा रूसी विमान घने जंगलों में हुआ क्रैश

(एजेन्सी)।

2025 में कई सारे प्लेन हादसे देखने को मिले हैं। इनमें सबसे बड़ा एयर इंडिया का अहमदाबाद प्लेन क्रैश था। लेकिन अब रूस से एक बड़ी दुखद खबर सामने आ रही है। वहां एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया है और लगभग सभी लोग मारे गए हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को चीन की सीमा के पास देश के पूर्वी क्षेत्र में 50 यात्रियों को ले जा रहा एक रूसी यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। रूसी विमान पूर्वी अमूर क्षेत्र में लापता हो गया था। रूसी हवाई यातायात नियंत्रण ने गुरुवार को कहा कि पूर्वी अमूर क्षेत्र में लगभग 50 लोगों को ले जा रहे एक एएन-24 यात्री विमान से उसका संपर्क टूट गया है। हालाँकि, बचाव दल ने 50 यात्रियों वाले लापता रूसी विमान के जलते हुए हिस्से का पता लगा लिया है।

शॉट समाचार आउटलेट के अनुसार, अंगारा एयरलाइन द्वारा संचालित यह विमान चीन की सीमा से लगे अमूर क्षेत्र के टिंडा शहर की ओर जा रहा था। गौरतलब है कि जब विमान का संपर्क टूटा, तब वह अपने गंतव्य से कुछ ही किलोमीटर दूर था। इंटरफैक्स और शॉट समाचार आउटलेट्स के अपडेट के अनुसार, लापता विमान एक एएन-24 यात्री विमान था। यह विमान चीन की सीमा से लगे अमूर क्षेत्र के टिंडा शहर की ओर जा रहा था। स्थानीय आपातकालीन मंत्रालय के अनुसार, चीन की सीमा से लगे अमूर क्षेत्र के शहर टिंडा के अपने गंतव्य के पास पहुँचते समय विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया।

क्षेत्रीय गवर्नर वासिली ओरलोव ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विमान में पाँच बच्चों सहित 43 यात्री और चालक दल के छह सदस्य सवार थे।

विजय देवरकोंडा की किंगडम का ट्रेलर 26 जुलाई को होगा रिलीज

(एजेन्सी)।

विजय देवरकोंडा एक बार फिर अपनी बहुप्रतीक्षित एक्शन से भरपूर फिल्म किंगडम के साथ पर्दे पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी घोषणा के साथ एक नया पोस्टर भी जारी किया। आधिकारिक ट्रेलर 26 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। ट्रेलर लॉन्च के लिए तिरुपति में एक बड़े कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। विजय देवरकोंडा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर नया पोस्टर शेयर किया और ट्रेलर रिलीज की तारीख का भी खुलासा किया। यह 26 जुलाई को रिलीज हो रही है। गौरतलब है कि काफी देरी के बाद, फिल्म आखिरकार 31 जुलाई को रिलीज हो रही है।

खबर है कि उन्हें डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालाँकि, अभिनेता के करीबी सूत्रों ने पुष्टि की है कि वह ठीक हो रहे हैं और जल्द ही काम पर लौटेंगे। इंडिया टुडे ने बताया है कि विजय अब ठीक हो रहे हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। "वह धीरे-धीरे अपने पैरों पर वापस आ रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, लेकिन अभिनेता जितना हो सके अपने काम के प्रति समर्पित रहने के लिए उत्सुक हैं। अब उनकी हालत में काफी सुधार है। वह घर पर ही हैं और इलाज का अच्छा असर हो रहा है। विजय प्रचार अभियान की शुरूआत करने के लिए तेलुगु में कुछ इंटरव्यू देंगे।" अभिनेता के एक करीबी सूत्र ने बताया।

"किंगडम" देवरकोंडा की अब तक की सबसे महंगी परियोजना भी है, जिसका निर्माण बजट लगभग 130 करोड़ रुपया है। इस फिल्म का निर्देशन गौतम तिन्ननुरी ने किया है, जो जर्सी में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, और इसका निर्माण नागा वामसी ने सीथारा एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले किया है। अभिनेता की हालिया फ्लॉप फिल्मों के बावजूद, अधिकार हासिल करने में नेटफ्लिक्स का भारी निवेश तिन्ननुरी और फिल्म की संभावित सफलता पर उसके विश्वास को दर्शाता है। किंगडम दो भागों में रिलीज होगी, पहला भाग 31 जुलाई, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। दूसरे भाग की शूटिंग का निर्णय पहले भाग को दर्शकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

चीनी खिलाड़ी को हराकर दिव्या देशमुख फिडे महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में

(एजेन्सी)। भारत की स्टार शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने फिडे महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के दूसरे गेम में चीनी झोंगयी टैन को मात दी। इसके साथ ही उन्होंने इस मिनी मैच 1.5-0.5 से जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस प्रक्रिया में दिव्या कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भी जगह बनाने वाली पहली भारतीय बन गईं। महिला कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट अगले साल होना है और उस टूर्नामेंट से मौजूदा महिला वर्ल्ड चैंपियन वेनजुन जू के प्रतिद्वंद्वी का फैसला होगा। बता दें कि, दिव्या पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं। चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त जोनर झू तत्कालीन हमवतन ग्रैंडमास्टर डी हरिका को क्वार्टर फाइनल में हराने के बाद दिव्या ने इस प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाए रखा और टैन के खिलाफ 101 चाल में जीत उनके बढ़ते शतरंज कौशल का प्रमाण था। दूसरे सेमीफाइनल में कोनेरू हम्पी ने 75 चाल में चीन की टॉप वरीयता प्राप्त टिंगजी लेई के साथ ड्रॉ खेला। हम्पी अब छोटे प्रारूप में लेई के खिलाफ टाई-ब्रेकर खेलेंगी। बता दें कि, 9 दिसंबर 2005 में नागपुर में जन्मीं दिव्या ने पांच साल की उम्र से शतरंज खेलना शुरू कर दिया था।

अब इंडिया में बैठकर अमेरिका में करें शॉपिंग

(एजेन्सी)।

ग्लोबल पेमेंट फर्म पेपल ने ऐलान किया कि उसने नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक टाई-अप किया है। यह टाई-अप पेपल वर्ल्ड के प्लैटफॉर्म पर यूपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए है जिससे इंटरनैशनल पेमेंट आसानी से हो सके। कंपनी ने कई ग्लोबल पार्टनरशिप का ऐलान किया है और यह उसी का एक हिस्सा है। अभी तक इसके लिए विदेशी सर्विसेज पर ही निर्भर रहना पड़ता था और इसके लिए यूजर के पास खास कार्ड और अकाउंट्स का होना जरूरी होता था। पेपल के नए प्लेटफॉर्म में यूपीआई के आने से घर बैठे विदेशों में शॉपिंग कर पाना अब चुटकियों का खेल रह जाएगा।

इस डेवलपमेंट पर बोलते हुए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा कि पेपाल वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर यूपीआई का एकीकरण यूपीआई के वैश्विक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह सीमा पार भुगतान को और अधिक सहज, सुरक्षित और समावेशी बनाने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह सहयोग विदेशों में भुगतान करने वाले भारतीय उपयोगकताओं के लिए सुविधा बढ़ाएगा और वैश्विक व्यवसायों और व्यापारियों को यूपीआई उपयोगकताओं के बढ़ते आधार का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा।

यह प्लेटफॉर्म पेपल और वेनमो के बीच इंटरऑपरेबिलिटी प्रदान करके शुरूआत करेगा और इसके शुरूआती लॉन्च में यूपीआई को शामिल करेगा। इसका मतलब है कि भारतीय उपभोक्ता अब अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों से खरीदारी कर सकते हैं और उस यूपीआई विकल्प का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं। पेपल होल्डिंग्स इंक की भारतीय सहायक कंपनी, पेपाल पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (पेपाल) को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से पेमेंट एग्रीगेटर-क्रॉस बॉर्डर-एक्सपोर्ट्स (पीए-सीबी-ई) के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के एक महीने बाद यह विकास हुआ है। बता दें कि एलन मस्क ने साल 1999 में एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी बनाई थी। इसका नाम एक्स डॉट कॉम था। यह कंपनी बाद में कन्फिनिटी नाम की दूसरी फर्म के साथ मर्ज हो गई थी। यही फर्म आगे चलकर पेपाल बनी।

सात्विक-चिराग की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, प्रणय को मिली हार

(एजेन्सी)। सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने गुरुवार को इंडोनेशिया के लियो रोली कर्नांडो और बगास मौलाना को सीधे गेम में हराकर चाइना ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि, एचएस प्रणय 65 मिनट तक चले पुरुष एकल के दूसरे दौरे के मैच में चीनी ताइपे के छठे वरीय चोऊ तिएन चेन से 21-18, 15-21, 8-21 से हार कर बाहर हो गए। विश्व की पूर्व नंबर एक भारतीय जोड़ी ने अपने धैर्य का अच्छा नमूना रेश करते हुए एक कड़े मुकाबले में आठवीं वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई जोड़ी पर 21-19, 21-19 से जीत हासिल की। सात्विक और चिराग को जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि दोनों ही गेम में पलड़ा इधर से उधर झुकता रहा। पहले गेम में इंडोनेशियाई जोड़ी ने पहले 8-6 और बाद में 14-12 की मामूली बढ़त बना ली थी, लेकिन भारतीय जोड़ी ने 14-15 के स्कोर के बाद लगातार पांच अंक जीतकर 19-16 से बढ़त बना ली और फिर पहला गेम अपने नाम कर दिया। वहीं दूसरे गेम में भी यही स्थिति रही। एक समय लियो और बगास 14-10 की बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन भारतीय जोड़ी ने वापसी करते हुए स्कोर 18-18 से बराबर कर दिया और आखिरी क्षणों में भी संयम बनाए रखते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की।

'रोड रूल्स, लाइफ टूल्स' अभियान के तहत करनाल में चला जागरूकता व चालान अभियान

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गुरुवार को करनाल में 'रोड रूल्स, लाइफ टूल्स' अभियान के अंतर्गत यातायात नियमों को लेकर जागरूकता शिविर और चालान ड्राइव का आयोजन किया गया। यह अभियान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्राधिकरण अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में तथा पुलिस विभाग के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन ने बताया कि यह मुहिम हालसा पंचकूला के निर्देश पर जिला के विभिन्न स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में चलाई जा रही है, ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति जनसाधारण को जागरूक किया जा सके।

इंस्पेक्टर राजेशलता द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अलीपुर खालसा में आयोजित शिविर में विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई और उन्हें इनका पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं और स्टाफ ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी ली।

पीएलवी अज्ञा पाल ने इंस्पेक्टर रोशन लाल, सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार व पुलिस टीम के साथ निसिंग के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भी जागरूकता शिविर आयोजित किए। इन शिविरों में भी विद्यार्थियों और शिक्षकों को यातायात नियमों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया। अभियान का उद्देश्य सड़क हादसों को कम करना और आमजन को जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करना है।

मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए अजय ने डीएम से लगाई गुहार, दिव्यांग जनों में छाई खुशी

संजना भारती संवाददाता

डुमरांव। डुमरांव अनुमंडल में दिव्यांग जनों को अब अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है। लंबे समय से क्षेत्र के दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय बक्सर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें भारी परेशानी होती थी। इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए रोगी कल्याण समिति के सदस्य अजय राय ने बुधवार की दोपहर एक बजे जिला पदाधिकारी डॉ. विद्यानंद सिंह को एक पत्र सौंपा। पत्र में अजय राय ने बताया कि डुमरांव एक महत्वपूर्ण अनुमंडल है, जिसमें सात प्रखंड शामिल हैं, जबकि बक्सर में केवल चार प्रखंड आते हैं। इसके बावजूद मेडिकल बोर्ड की सुविधा केवल बक्सर में उपलब्ध है। सुनिए क्या कुछ कहा अजय राय ने अजय ने बताया कि इससे डुमरांव क्षेत्र के दिव्यांगों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समय, धन और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक संवेदनशीलता दिखाते हुए डीएम डॉ. विद्यानंद सिंह ने इस विषय पर सकारात्मक रुख अपनाया और डुमरांव अनुमंडल अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए आश्वासन दिया। यदि यह पहल धरातल पर उतरती है तो न सिर्फ डुमरांव के दिव्यांगों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रमाण पत्र प्रक्रिया भी सुगम होगी। इस मांग को सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए स्थानीय लोगों ने भी समर्थन दिया है। उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन जल्द ही ठोस कदम उठाकर मेडिकल बोर्ड का नियमित गठन करेगा, जिससे डुमरांव अनुमंडल के हजारों दिव्यांगों को घर के पास ही आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

किसानों को समय पर मिले यूरिया, न हो कोई कालाबाजारी: डीसी उत्तम सिंह

■ कालाबाजारी करने वालों पर तत्काल होगी सख्त से सख्त कार्रवाई

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। डीसी उत्तम सिंह ने गुरुवार को लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हाल में यूरिया के वितरण को लेकर कृषि विभाग, फर्टिलाइजर सप्लायर एजेंसी, फर्टिलाइजर उत्पादन कंपनियों के अधिकारियों व प्राइवेट सप्लायर की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को समय पर यूरिया मिले और किसी तरह की कोई कालाबाजारी न हो। यदि कोई ऐसा करता मिले तो उसकी तत्काल सूचना दें, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ-साथ उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि वह भी यूरिया का अनावश्यक स्टॉक न करें। यूरिया की कोई कमी नहीं है। किसान को जितनी जरूरत है, उतना ही यूरिया खरीदे। जिला में जितनी डिमांड है, उतना यूरिया उपलब्ध है। जैसे ही उत्पादन कंपनियों द्वारा यूरिया की सप्लाई आती है, तत्काल उसे विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है।

डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि यूरिया के वितरण में किसी तरह की कोई कालाबाजारी न हो। सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर पर भी कृषि विभाग पैनी नजर रखे। सरकार द्वारा तय मापदंडों पर ही यूरिया का वितरण हो। यदि कोई प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर भी कालाबाजारी करता मिले, तो तत्काल जानकारी दें, सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि पैक्स अपने यहां ग्राम पंचायतों व अन्य जगहों पर यूरिया आदि के स्टॉक की व्यवस्था करें ताकि पीक सीजन में उनकी डिमांड पूरी हो सके। यदि वह पहले से स्टॉक रखेंगे तो आसानी से फर्टिलाइजर की उपलब्धता होगी। वहीं बैठक में जानकारी देते हुए कृषि विभाग के उपनिदेशक वजीर सिंह ने बताया कि जिला में अभी तक 83 एमटी यूरिया आया है। जो पिछली बार से अधिक है। उन्होंने फर्टिलाइजर कंपनियों से समय पर स्टॉक शेयर करने की अपील कि ताकि वहां समय रहते स्टाफ की ड्यूटी लगाई जा सके।

इस दौरान इफको से डॉ. निरंजन यादव, कृभको, एनएफएल, श्रीराम फर्टिलाइजर, जंबल फर्टिलाइजर, हैफेड, पैक्स के अधिकारी मौजूद रहे।

बेगूसराय में अंचलाधिकारी को जान मारने की धमकी, मामला दर्ज

खून कर देंगे की धमकी देकर सीओ चेंबर में घुसा बुजुर्ग

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मिन्टू कुमार

वीरपुर(बेगूसराय)। बेगूसराय के वीरपुर अंचल कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। अंचलाधिकारी भाई वीरेंद्र ने दो लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। अंचलाधिकारी द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के मुताबिक, वीरपुर पश्चिम पंचायत वार्ड संख्या-5 निवासी स्व.मोहन राय के पुत्र महावीर राय मंगलवार को अपराह्न लगभग 2 बजे उनके कार्यालय पहुंचे और बिना अनुमति उनके चेंबर में प्रवेश कर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया।

आरोप है कि महावीर राय ने गमछे से कुछ निकालने की कोशिश की, जिससे अंचलाधिकारी भयभीत हो गए। जब उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा और शांति से अपनी बात रखने की अपील की तो महावीर राय आक्रामक हो गए और धमकी देने लगे। अंचलाधिकारी का कहना है कि जब उन्होंने पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करने की कोशिश की तो महावीर राय ने धमकी दी कि फोन करोगे तो खून कर देंगे। उन्होंने बताया कि महावीर राय की उम्र भले ही अधिक है, लेकिन उनका व्यवहार बेहद आक्रामक और डराने वाला है, जो कार्यालय के कार्य माहौल को बाधित करता है। घटना के समय अंचल गार्ड अवधेश कुमार सिंह और सुधीर कुमार सिंह भी मौके पर मौजूद थे।

इतना ही नहीं, अंचलाधिकारी ने यह भी बताया कि करीब एक माह पूर्व महावीर राय और उनके छोटे भाई युगल किशोर राय ने भी इसी तरह कार्यालय में घुसकर गाली-गलौज और धमकी दी थी। इस संबंध में वीरपुर थाना अध्यक्ष सह पुलिस अवर निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि अंचलाधिकारी के आवेदन पर थाना कांड संख्या 159/25 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने महावीर राय को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है।

हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

संजना भारती संवाददाता

मनोज कुमार बिन्द

बारा। श्री हरिधाम सेवा समिति गोठी बेलसरा प्रयागराज के पीठाधीश्वर एवं श्री निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी विनयानन्द गिरी महाराज जी के द्वारा हरियाली अमावस्या के मौके पर एक महत्वपूर्ण वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी विनयानन्द गिरी महाराज जी ने भक्तों के साथ मिलकर हरे वृक्ष लगाए और लोगों को फलदाई वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया। वृक्षारोपण महामंडलेश्वर स्वामी विनयानन्द गिरी महाराज जी ने भक्तों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे और मां के नाम एक वृक्ष लगाने का संकल्प लेते हुए सेवा करने का भी संकल्प लिया। हरियाली अमावस्या का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई दिया यह पर्व पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति की पूजा का एक महत्वपूर्ण अवसर है। हरियाली अमावस्या का आध्यात्मिक महत्व भी है जिसमें लोग भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि लोगों को वृक्षारोपण के महत्व के बारे में भी शिक्षित करेगा।

संत सीचेवाल ने संसद में रूस में फंसे भारतीयों का मुद्दा उठाया

रूसी सेना में भर्ती 12 भारतीय अब भी लापता

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

दिल्ली/चंडीगढ़/सुल्तानपुर लोधी। संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने संसद में प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्रालय से रूस की सेना में फंसे भारतीयों का मुद्दा गंभीरता से उठाया। संसद का चल रहा मानसून सत्र भले ही हंगामों की भेंट चढ़ रहा हो, लेकिन सांसदों द्वारा पूछे गए लिखित सवालों का जवाब सरकार को संसद में देना ही पड़ता है।

संत सीचेवाल ने विदेश मंत्रालय से पूछा कि रूस में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में विस्तृत जानकारी क्यों उनके परिवारों तक नहीं पहुंच रही? उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इन भारतीय नागरिकों को मदद उपलब्ध कराने, उनकी सुरक्षित वापसी, यात्रा प्रबंध और विदेश में कानूनी सहायता जैसे संवेदनशील मामलों में सरकार क्या कदम उठा रही है? साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि रूस में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी में सरकार को किन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? संसद के मानसून सत्र में संत सीचेवाल के इस लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए विदेश मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि रूसी सशस्त्र सेनाओं में 127 भारतीय नागरिक मौजूद थे। इनमें से 98 लोग वापस आ चुके हैं, जबकि 13 भारतीय नागरिक अब भी रूसी सशस्त्र सेनाओं में हैं, जिनमें से 12 भारतीयों के रूसी पक्ष द्वारा लापता होने की पुष्टि की गई है। विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि संबंधित रूसी अधिकारियों से शेष/लापता व्यक्तियों के बारे में अद्यतन जानकारी देने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। जिन भारतीय नागरिकों की सेवाएं रूसी सेना में समाप्त हो चुकी हैं, उनकी वापसी में भारतीय दूतावास ने सहायता प्रदान की है, जिसमें यात्रा दस्तावेजों की सुविधा और आवश्यकता पड़ने पर हवाई टिकट उपलब्ध कराना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि विदेशों में सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सहायता की किसी भी अर्जी पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में संत सीचेवाल ने दो परिवारों के सदस्यों को मास्को जाने के लिए टिकटें भी दिलवाई थीं, जिनके परिजन रूसी सेना में भर्ती थे। इन दो युवकों को रूस में कोई परेशानी न हो, इसके लिए भारतीय दूतावास के नाम संत सीचेवाल ने पत्र भी लिखा था, ताकि इन युवकों की मदद की जा सके और वे अपने परिजनों को खोज सकें।

अकाली लैंड पूलिंग का विरोध कर रहे हैं, जिसका मास्टर प्लान खुद बनाकर गए थे-अमन अरोड़ा

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा पेश की गई लैंड पूलिंग नीति पर विरोधी पार्टियों द्वारा की जा रही बेबुनियाद और झूठी बयानबाजी पर निशाना साधते हुये पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आप प्रदेश प्रधान श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि नयी लैंड पूलिंग नीति शिरोमणि अकाली दल (अकाली)-भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बनाये गये फ्रेमवर्क के आधार पर बनाई गई है।

यहां पंजाब भवन में प्रैस कान्फ्रेंस दौरान श्री अमन अरोड़ा ने लैंड पूलिंग नीति को पंजाब के लिए बहुत अहम और लाभदायक करार देते हुये कहा कि यह नीति पारदर्शिता, निष्पक्षता पर आधारित है और जन कल्याण ही इसकी मुख्य प्राथमिकता है। यह नीति संगठित और योजनाबद्ध विकास को उत्साहित करेगी, इसके इलावा जमीन मालिकों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाएगी।

विरोधी पार्टियों की बेबुनियाद और झूठी बयानबाजी का पर्दाफाश करते हुये श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों की पिछली कार्यवाहियां नईं लैंड पूलिंग नीति के सम्बन्ध में उनके मौजूदा रूख के बिल्कुल विपरीत हैं। उन्होंने बताया कि अकाली-भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने एसएएस नगर (मोहाली), अमृतसर, तरन तारन और होशियारपुर समेत कई शहरों में मास्टर प्लानों के बारे नोटिफिकेशन जारी किये थे। इन नोटीफिकेशनों ने रिहायशी और व्यापारिक विकास के लिए सैंकड़े एकड़ जमीन घोषित की और निजी डिवैलपरों को कॉलोनियां बनाने की अनुमति भी दी। अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों की तरफ से डिफालटर बिल्डरों की पुशतपनाही के कारण पंजाब में लगभग 20,000 एकड़ क्षेत्र पर गैर-कानूनी कॉलोनियां बन गयी हैं, जहाँ सिवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाईटों और अन्य बुनियादी नागरिक सहूलतों की अनुपस्थिति के कारण खरीददारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोहाली क्षेत्र में विकास हुआ है। 2009 से 2021 तक, कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों ने मोहाली में 3735 एकड़ जमीन एक्वायर की थी। श्री अरोड़ा ने पूछा कि यदि मोहाली योजनाबद्ध विकास और अत्याधुनिक सहूलतों का हकदार है तो बाकी पंजाब क्यों नहीं? होशियारपुर, तरनतारन या फिरोजपुर क्यों नहीं?

नईं नीति की मुख्य विशेषताओं को उजागर करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि नयी लैंड पूलिंग नीति पिछली नीतियों के मुकाबले अधिक किसान-हितैषी और जन-केंद्रित है। अब जमीन की खरीद-फरोख़्त पर कोई पाबंदी नहीं है। किसान अपनी जमीन खुद डिवैल्प कर सकते हैं या सरकारी या निजी डिवैलपरों के साथ हिस्सेदारी कर सकते हैं, पहले तीन सालों के लिए 50,000 रुपए मुआवजा और जमीन के कब्जे के बाद 1 लाख रुपए और रिहायशी और व्यापारिक प्लाटों की अदला- बदली का विकल्प भी नीति में उपलब्ध है।

श्री अमन अरोड़ा ने माँग की कि अकाली-भाजपा और कांग्रेस को पंजाब के लोगों से उनको गुमराह करने और गैर-कानूनी कॉलोनियों को उत्साहित करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप के नेतृत्व वाली सरकार योजनाबद्ध विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण के लिए वचनबद्ध है। विरोधी पक्ष के दोष बेबुनियाद और स्वार्थ से प्रेरित हैं।

डॉ. बलजीत कौर द्वारा विभाग में नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज पंजाब भवन, चंडीगढ़ में विभाग के नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि विभाग की ओर से चलाए जा रहे भर्ती अभियान के अंतर्गत 10 आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, 6 सुपरिटेंडेंट (बाल गृह) और 1 ज़िला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले विभाग द्वारा 97 आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो विभाग की कार्यक्षमता और जनकल्याण से संबंधित कार्यों को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नव नियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने उन्हें प्रेरित किया कि वे पूरी ईमानदारी, समर्पण और सहानुभूति के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

मंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग समाज के हर वर्ग से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, और नए कर्मचारी सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के सक्षम नेतृत्व में पंजाब सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए वचनबद्ध है। अब तक 54,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियाँ प्रदान की जा चुकी हैं।

अंत में मंत्री ने कहा कि नव नियुक्त कर्मचारी सरकारी नीतियों और जमीनी स्तर के लाभार्थियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए। उनकी सक्रिय और प्रभावशाली भागीदारी से यह सुनिश्चित होगा कि योजनाएँ जरूरतमंदों तक समय पर और पारदर्शिता के साथ पहुँच सकें। इस दिशा में राज्य की सामाजिक संरचना और अधिक सुदृढ़ बनेगी।

इस अवसर पर विभाग की विशेष मुख्य सचिव श्रीमती राजी.पी श्रीवास्तव, निदेशक डॉ. शेना अग्रवाल, विशेष सचिव श्री केशव हिंगोनिया, संयुक्त सचिव श्री आनंद सागर शर्मा, अतिरिक्त निदेशक श्री चरनजीत सिंह, और उप निदेशक श्री सुखदीप सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने भी नव नियुक्त कर्मचारियों को बधाई दी और विभाग की सेवा निभाने के लिए उन्हें प्रेरित किया।

पंजाब भर में अब आसान होगा नक्शे पास कराना-हरदीप मुंडियां

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। राज्य में शहरी विकास को योजनाबद्ध और सुचारू बनाने और निर्माण सम्बन्धी नियमों में पारदर्शिता यकीनी बनाने की तरफ बड़ा कदम उठाते हुये मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने शहरों के लिए एकीकृत इमारती उप-नियम (यूनिफाईड बिल्डिंग बायलाज) बनाने का फैसला किया है।यहाँ पंजाब भवन में प्रैस कान्फ्रेंस को संबोधन करते हुये आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि इस फैसले से शहर निवासियों और दूसरे भागीदारों की काफी देर की लम्बित माँग पूरी होगी। उन्होंने बताया कि इन बायलाज का मसौदा अधिकारिक वैबसाईटों www.puda.gov.in और www.enaksha.lgpunjab.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है जिससे लोगों से सुझाव लिए जा सकें। उन्होंने राज्य निवासियों को 30 दिनों के अंदर अपने सुझाव देने के लिए न्योता दिया।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शहरों में भविष्योन्मुखी और एकसमान बिल्डिंग बनाने के लिए यूनिफाईड बिल्डिंग बायलाज बनाने के लिए लोगों के परामर्श लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बायलाज को सलाह-मशवरे और लोगों के सुझावों के साथ तैयार किया जा रहा है।

स. मुंडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य निवासियों को आसान, सुलभ और पारदर्शी सेवाएं देना मुख्य एजेंडा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बिल्डिंग बायलाज सबसे जटिल और कठिन मसला था जिस सम्बन्धी लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि डिवैलपरों, आर्किटेक्टों, इंजीनियरों जैसे अलग-अलग भागीदारों को बायलाज बनाने की प्रक्रिया में शामिल करके यह यकीनी बनाया जा सकेगा कि बायलाज उनकी जरूरतों और उम्मीदों को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि इन बिल्डिंग बायलाज को लागू करके पंजाब, सरल बिल्डिंग बायलाज वाला और आसान कारोबार करने वाला, टिकाऊ शहरीकरण और पारदर्शिता को उत्साहित करने वाला देश का पहला राज्य बन जायेगा।

यूनिफाईड बिल्डिंग बायलाज बनाने के मंतव्य संबंधी बात करते हुये स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को सुचारू बनाया जा रहा है। पंजाब में सभी विकास प्राधिकरणों और निगमों में बिल्डिंग बायलाज को एकसमान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बायलाज को लोगों के अनुकूल, समझने में आसान और पालना करने योग्य बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री ने विशेष के तौर पर कहा कि नये पेश किये गए बायलाज में लाल फीताशाही को घटाया गया है और कारोबार करने की सुविधा को उत्साहित करते हुए अनावश्यक नौकरशाही रुकावटों को खत्म किया गया है। इसी तरह टिकाऊ शहरीकरण को उत्साहित किया गया और वातावरण के अनुकूल और भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकास के तरीकों को उत्साहित किया गया है। उन्होंने कहा कि इमारत के नियमों में छूट जैसे कि फ्लोर एरिया रेशो (एफ.ए.आर) और ग्राउंड कवरेज बढ़ायी गई है। उन्होंने कहा कि इससे कुदरती स्त्रोतों पर आधारित ग्रीन बिल्डिंगें बनाने वाले डिवैलपरों को प्रोत्साहित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कारोबार करने को आसान (इज आफ डुईंग बिजनस) करने के उद्देश्य के अंतर्गत तैयार किये सरल नियम और सुचारू प्रक्रियाएं निवेश को आकर्षित करेंगी और आर्थिक विकास को उत्साहित करेंगी। उन्होंने बताया कि आनलाइन पोर्टल के द्वारा जनता के साथ सलाह-मशवरा किया जायेगा, जो शिकायत प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को यकीनी बनाऐगा।

पंजाब सरकार द्वारा मैडीकल और डैंटल इंटर्नों और रैजीडैंटों के मानभत्ते में उल्लेखनीय बढ़ोतरी: हरपाल सिंह चीमा

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को मजबूत करने की अटूट वचनबद्धता पर जोर देते हुये पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के सरकारी मैडीकल और डैंटल कालेजों में इंटर्नों, जूनियर रैजीडैंटों और सीनियर रैजीडैंटों के प्रति महीना मानभत्ते (स्टाईफंड) में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी का ऐलान किया। यहाँ जारी एक प्रैस बयान में यह जानकारी देते हुये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वर्तमान में पंजाब के सरकारी मैडीकल और डैंटल कालेजों में इंटर्नों के 907, जूनियर रैजीडैंटों के 1408 और सीनियर रैजीडैंटों के 754 मंजूरशुदा पद हैं। उन्होंने कहा कि इंटर्नों के लिए मानभत्ता 15,000 रुपए से बढ़ा कर 22,000 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। जूनियर रैजीडैंटों के लिए नये मानभत्ता ढांचे में मौजूदा 67,968 रुपए प्रति महीना से बढ़ कर पहले साल में 76,000 रुपए, दूसरे साल में 77,000 रुपए और तीसरे साल में 78,000 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह, सीनियर रैजीडैंटों को उनके मौजूदा 81,562 रुपए प्रति महीना से बढ़ा कर पहले साल में 92,000 रुपए, दूसरे साल में 93,000 रुपए और तीसरे साल में 94,000 रुपए मिलेंगे। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए जरुरी स्त्रोत उपलब्ध कराने के प्रति राज्य सरकार के समर्पण को दोहराया।

जिला नगर आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने सफाई अधिकारियों व नपा सचिवों के साथ बैठक कर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों पर की समीक्षा

आगामी सर्वेक्षण में बेहतर रैंक लाने के लिए सचिवों को कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों के बाद अब आगामी सर्वेक्षण में ओर बेहतर रैंकिंग लाने के मकसद को लेकर जिला नगर आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने नगर निगम की सफाई शाखा एवं जिला की नगर पालिकाओं के अधिकारियों के साथ गुरूवार को एक बैठक की।

बैठक में अतिरिक्त निगम आयुक्त अशोक कुमार, कार्यकारी अभियंता ओ.पी. करदम, मुख्य सफाई निरीक्षक सुरेन्द्र चोपड़ा, नगर पालिका सचिव तथा सफाई शाखा से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे। जिला नगर आयुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से एक-एक कर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की समीक्षा की और नपा सचिवों को निर्देश दिए कि वह डोर टू डोर कूड़ा उठान, पृथक्करण, कूड़ा निस्तारण, रिहायशी व वाणिज्यिकी क्षेत्रों की साफ-सफाई तथा सामुदायिक व जन शौचालयों की सफाई जैसे बिन्दूओं की रोजाना मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि जिन-जिन बिन्दू पर कम अंक मिले हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए।

कार्य योजना करें तैयार- उन्होंने नपा सचिवों को आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर अंक अर्जित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें सभी मुख्य बिन्दूओं को शामिल किया जाए और उनकी साप्ताहिक समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जिस बिन्दू पर कम अंक मिले हैं, उसे कैसे सुधारा जाएगा और क्या-क्या नए कार्य किए जाने हैं, जिनसे हम बेहतर रैंक ला सकें, यह सब कार्य योजना में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त मासिक, त्रिमासिक व छः मास में स्वच्छता को लेकर क्या-क्या कार्य किए जाने हैं, उनका लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

सफाई कर्मचारियों को दें लक्ष्य- उन्होंने कहा कि आत्म निर्भर वार्ड के तहत एक-एक वार्ड को लेकर उसमें कूड़ा पृथक्करण करवाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां जोर-शोर से चलाई जाएं। एकल प्रयोग प्लास्टिक और गंदगी के चालान किए जाएं। बल्क वेस्ट जेनरेटर का निरंतर दौरा किया जाए। सामुदायिक व जन शौचालय साफ-सुथरे रहें। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी कार्यों के लिए कर्मचारियों को लक्ष्य दिया जाए। सी एंड डी वेस्ट निस्तारण के लिए ट्रैक्टर-ट्राली को अधिकृत करें। उन्होंने सख्त निर्देश देते कहा कि मोटीवेटर्स से पूरा काम लिया जाए। अगर कोई मोटीवेटर कार्य में लापरवाही करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाए।

बाजारों में न होने दें अतिक्रमण- उन्होंने बाजारों व सडकों को अतिक्रमण मुक्त करने पर जोर देते कहा कि नगर निगम अधिकारी एवं नपा सचिव शहर में अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाएं।

सडक पर पीली पट्टी लगाई जाए। सभी दुकानदार व फड़ी संचालकर उसी के अंदर रहे। कोई भी सडक पर आगे तक सामान न रखे। उन्होंने सचिवों से कहा कि जगह चिन्हित कर वेंडिंग जोन बनाए जाएं और रेहड़ी-फड़ी वालों को वहां भेजा जाए। इसके साथ-साथ शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए भी ड्राइव चलाई जाए। अगर कोई व्यक्ति पशु छोड़ते पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।

विधायक जगमोहन ने सुनी जनसमस्याएं, मौके पर दिए समाधान के निर्देश

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। विधायक जगमोहन आनंद ने गुरुवार को अपने कैंप कार्यालय पर लोगों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश देकर समाधान करवाया। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा ही उनकी प्राथमिकता है और कोई भी व्यक्ति बिना झिझक अपनी समस्या लेकर उनसे मिल सकता है।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनसेवा में लगातार सक्रिय है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में करनाल में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना पर्ची और बिना खर्ची की नीति से युवाओं को सीधी भर्ती का लाभ मिल रहा है, इसी कारण सीईटी परीक्षा के प्रति युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। विधायक ने भरोसा दिलाया कि सरकार सबका साथ-सबका विकास के संकल्प के साथ आमजन की समस्याओं का समाधान निरंतर करती रहेगी।

सैनिक स्कूल कुंजपुरा ने मनाया 65वां स्थापना दिवस, मेजर जनरल संजय हुडा बोले-यह गौरवशाली इतिहास की जीवंत मिसाल

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। देश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में शुमार सैनिक स्कूल कुंजपुरा का 65वां स्थापना दिवस वीरवार को पूरे गर्व और भव्यता के साथ मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्य अतिथि मेजर जनरल संजय हुडा (सेना मेडल), चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर 2 कोर, एवं विशिष्ट अतिथि ब्रिगेडियर एच.एस. संधू (सेना मेडल), डिप्टी जी.ओ.सी. सब एरिया ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर समारोह का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम का औपचारिक आयोजन मानेकशा सभागार में हुआ, जहां विद्यालय के प्रधानाचार्य कप्तान गुरबीर सिंह (भारतीय नौसेना) ने अतिथियों का स्वागत करते हुए वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि कैसे छात्र और शिक्षक मिलकर इस गौरवशाली संस्था की प्रतिष्ठा को निरंतर ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। समारोह में छात्र पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और शिक्षा व खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। सदन अध्यक्षों को भी उनके नेतृत्व कौशल के लिए सम्मानित किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए मेजर जनरल संजय हुडा ने कहा, सैनिक स्कूल कुंजपुरा केवल एक स्कूल नहीं, बल्कि भारत के गौरवशाली सैन्य इतिहास की नींव है। यहां से निकले हुए छात्र देश की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

प्रधानाचार्य कप्तान गुरबीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि स्कूल आने वाले वर्षों में और भी स्वर्णिम इतिहास रचेगा। उप-प्रधानाचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल निर्मलजीत सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन दिया और स्क्वाड्रन लीडर सोनिया शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन कुशलता से संभाला।

वैश्विक लीडर अपूर्व शर्मा ने छात्रों में भरी नई ऊर्जा, करनाल इंटरनेशनल स्कूल में दिया सफलता का मंत्र

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी करनाल। करनाल इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को एक प्रेरणादायक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें केओएनई, स्टॉकहोम, स्वीडन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री अपूर्व शर्मा ने छात्रों से सीधा संवाद किया। IIT बॉम्बे और मिशिगन यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र श्री शर्मा ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 600 से अधिक छात्र-छात्राओं को सफलता, अनुशासन और आत्मविकास के मंत्र दिए।

श्री शर्मा ने अपने संघर्षों से लेकर अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट जगत में सफलता की कहानी साझा करते हुए बताया कि एक अच्छा इंसान बनना, स्पष्ट लक्ष्य तय करना और समर्पण के साथ मेहनत करना ही असली सफलता की कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत, चरित्र निर्माण और आत्मविश्वास का महत्व भी समझाया।

नीट, जेईई और एनडीए जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर उन्होंने समय प्रबंधन, स्मार्ट अध्ययन तकनीक और आत्म-प्रेरणा के उपाय बताए। छात्रों ने इंटरएक्टिव सत्र में खुलकर प्रश्न पूछे, जिनके उन्होंने सरल और प्रेरक उत्तर दिए।

इस अवसर पर विद्यालय अध्यक्ष कर्नल अरुण दत्ता, जेनेसिस क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जितेन्द्र अहलावत और विद्यालय निदेशक श्री प्रकाश जोशी ने श्री शर्मा का स्वागत किया।

कर्नल अरुण दत्ता ने अपने धन्यवाद संबोधन में कहा, 'यह सत्र केवल एक भाषण नहीं था, बल्कि छात्रों के जीवन को दिशा देने वाला अनुभव था।' कार्यक्रम का समापन छात्रों की तालियों और प्रेरणा से ओत-प्रोत वातावरण में हुआ। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि आगे भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से छात्रों को वास्तविक जीवन के आदर्शों से जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा।

हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी के नथेरा गांव में नए उप स्वास्थ्य केंद्र की दी मंजूरी

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी के नथेरा गांव में नए उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध पंचायती भूमि पर स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना होगा। यह केंद्र स्थानीय आबादी के लिए मातृ एवं शिशु देखभाल, टीकाकरण, रोग निवारण और बुनियादी उपचार जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि यह परियोजना मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा का हिस्सा है, जो पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह पहल सिर्फ बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के बारे में है। स्वास्थ्य सेवा को घर के नजदीक लाकर, सरकार दूर के अस्पतालों पर बोझ कम कर रही है और स्वास्थ्य सेवा को अधिक समावेशी बना रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा में किसी भी परिवार को बुनियादी चिकित्सा सहायता के लिए दूर न जाना पड़े। यह नया केंद्र उसी दिशा में एक कदम है। नए उप स्वास्थ्य केंद्र में एक पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीएचडब्ल्यू-एम), एक महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एमपीएचडब्ल्यू-एफ) और एक हेल्पर होगा।

डॉ. भीम राव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में रोजगार मेला 28 जुलाई को: जिला रोजगार अधिकारी

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार कैथल। जिला रोजगार अधिकारी ममता कुमार ने बताया कि आगामी 28 जुलाई को सुबह 10 बजे कार्यालय द्वारा जिले के युवाओं को रोजगार व अप्रैंटिसशिप के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेले में एकांश मोटर्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, पुखराज, एलआईसी जीवन बीमा, भारत फाइनेंशियल इन्क्लूशन व एसआईएस सिक्योरिटी आदि प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं का चयन करेंगी। योग्यता 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट व आईटीआई के इच्छुक प्रार्थी नौकरियों के पंजीकरण हेतु इस जॉब फेयर में आईटीआई के विभिन्न ट्रेड, सेल्स ऑफिसर, वेलनेस एडवाइजर, जॉब व सेल्स कन्सल्टेन्ट आदि पदों के लिए आग ले सकते है। इस मेले का आयोजन कई विभागों के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। यह मेला उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो अच्छे रोजगार की तलाश में है।

तीन दिवसीय कांवड़ शिविर व भंडारे का हुआ समापन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग असन्ध। श्री महादेव सेवा दल द्वारा सावन की शिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री सालासर खाटू श्याम मंदिर में कांवड़ियों के लिए लगाए गए तीन दिवसीय कांवड़ शिविर व भंडारे का समापन हुआ। भंडारे में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर प्रसाद ग्रहण किया। श्री महादेव सेवा दल के प्रधान संजय भट्ट ने कहा कि धार्मिक आयोजन से समाज में आपसी एकता व भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। इस तरह के कार्यक्रम समाज में निरंतर होते रहने चाहिए। श्री महादेव सेवा दल के कोषाध्यक्ष सतबीर मुनिम ने कहा कि हर वर्ष समिति द्वारा शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया जाता है। जिसमें सभी सदस्य व नगरवासी सहयोग करते है। उन्होंने कहा कि लोगों को धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस अवसर पर समाजसेवी केवल मदान, नरेश गोयल, मंदिर प्रधान दर्शन शर्मा, अनिल भट्ट, नवीन चावला, रोहित गर्ग, विनोद बिंदल, अनित चोपड़ा, केवल कृष्ण आदि मौजूद रहे।

जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में प्रवेश के लिए 29 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन: सुचिता गुप्ता

एसबी संवाददाता

कैथल। जवाहर नवोदय विद्यालय, तितरम की प्राचार्या सुचिता गुप्ता ने बताया कि पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय कैथल के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छठी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई 2025 तक किया जा सकता है। यह विद्यालय भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित पूर्णतः आवासीय एवं सह-शैक्षणिक है। आगामी 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार को परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा कैथल जिले के विभिन्न केंद्रों पर करवाई जाएगी। जिन विद्यार्थियां ने जिला कैथल के सरकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय के कक्षा पांच में अध्ययन कर रहे हैं, कैथल जिला के निवासी हैं और जिनकी आयु 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के (दोनों तिथियां सम्मिलित) मध्य है, वे सभी विद्यार्थी परीक्षा में आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। प्राचार्य सुचिता गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज फोटो, माता अथवा पिता के हस्ताक्षर, छात्र तथा छात्रा का जाति प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार की सूची वाला ही मान्य होगा। पंजीकरण नवोदय विद्यालय की वेबसाईट www.navoday.gov.in पर कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए हेल्पडेस्क मोबाईल नंबर 8766265684, 9413842851, 9413258161, 9306409373 पर सुबह 9 बजे से सायं 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

सीईटी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी: डीसी प्रीति

27 लोकेशन पर बनाए गए हैं 33 परीक्षा केंद्र, 34 हजार 34 परीक्षार्थी देंगे सीईटी परीक्षा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार कैथल। डीसी प्रीति ने कहा कि सीईटी परीक्षा का आयोजन 26 व 27 जुलाई को चार शिफ्टों में होगा। जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए जिला में 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिन पर 34 हजार 34 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 26 जुलाई को सुबह के सत्र में 8505 अभ्यार्थी, सायं कालीन सत्र में 8506 अभ्यार्थी परीक्षा देंगे। इसी प्रकार 27 जुलाई को सुबह के सत्र में 8511 अभ्यार्थी, सायं कालीन सत्र में 8512 अभ्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को शांति पूर्ण, निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने को लेकर डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं वहीं फ्लाईंग स्कवायड की टीमें गठित की गई हैं। बाहर जिलों से कैथल आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए तथा कैथल जिला से चंडीगढ़ व पंचकूला जाने वाले अभ्यार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में बसों की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।

27 लोकेशन पर बनाए गए 33 परीक्षा केंद्र: अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढांड रोड कैथल, आर्यन इंटरनेशनल स्कूल ढांड रोड कैथल, इंडस पब्लिक स्कूल ढांड रोड कैथल, दिल्ली पब्लिक स्कूल अंबाला रोड कैथल, डॉ भीमराव अंबेडकर राजकीय कॉलेज गांव जगदीशपुरा अंबाला रोड कैथल, हिंदू गर्ल्ज सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला रोड कैथल, राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलाई बाजार कैथल, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैथल, गुरु तेग बहादुर खालसा पब्लिक स्कूल नानकपुरी कॉलोनी खुराना रोड कैथल, हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज नजदीक रणधीर सिनेमा कैथल, इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय करनाल रोड कैथल, इंदिरा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढांड रोड कैथल, जाट कॉलेज ऑफ एजुकेशन करनाल रोड कैथल, जाट कॉलेज करनाल रोड कैथल, जाट शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल करनाल रोड कैथल, जाट सीनियर सैकेंडरी स्कूल कैथल, जवाहर नवोदय विद्यालय गांव तितरम जींद रोड कैथल, एमडीएन ग्लोबल स्कूल गुलमोहर सिटी के पीछे डयोढ़ खेड़ी कैथल, सन शाइन पब्लिक स्कूल जींद रोड कैथल, ओएसडीएवी पब्लिक स्कूल खुराना रोड कैथल, शैम रॉक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुराना रोड कैथल, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल खुराना रोड कैथल, आरकेएसडी कॉलेज अंबाला रोड कैथल, आरके पब्लिक स्कूल कैथल, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जखोली अड्डा कैथल, राधाकृष्णन सीनियर सेकेंडरी स्कूल नई अनाज मंडी कैथल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

उपायुक्त कैथल प्रीति।

10 क्लस्टर में बांटा जिला: डीसी प्रीति ने बताया कि कैथल जिला वासियों के परीक्षा केंद्र पंचकूला व चंडीगढ़ में बनाए गए हैं। कैथल जिला से करीब 65 हजार अभ्यार्थी चंडीगढ़ व पंचकूला में परीक्षा देने जाएंगे। परीक्षार्थियों को ले जाने व वापस लाने के लिए स्पेशल बसों की व्यवस्था की गई है। जिले को 10 क्लस्टर में बांटा गया है। इसमें पूंडरी, ढांड, कैथल, राजौंद, कलायत, चीका, कसान, सांघन, सीवन तथा पाई शामिल हैं। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 26 जुलाई को सुबह के सत्र में है उनके लिए सुबह 3 बजे से बसें पंचकूला व चंडीगढ़ के लिए रवाना होनी शुरू हो जाएंगी। जिन परीक्षार्थियों की सायं कालीन सत्र में परीक्षा हैं उनके लिए सुबह 8 बजे से बस रवाना होनी शुरू हो जाएंगी।

चंडीगढ़ व पंचकूला में यहां होंगी बसों की पार्किंग: चंडीगढ़ में आईएसबीटी बस स्टैंड सेक्टर 17 के पीछे ग्राउंड में परीक्षार्थियों को छोड़ेंगी, जहां से आगे शटल बसें परीक्षा केंद्र तक लेकर जाएंगी। इसी प्रकार पंचकूला में धरना स्थल सेक्टर 5 पंचकूला व बस स्टैंड पंचकूला के पीछे ग्राउंड में बसों की व्यवस्था की गई है।

जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम किया स्थापित: डीसी प्रीति ने बताया कि जिला सचिवालय के द्वितीय तल स्थित कमरा नंबर 324 को कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए तीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। टोल फ्री नंबर 1800-180-132, 01746-298928 तथा 01746-294040 पर कॉल करके परीक्षा से संबंधित जानकारी ले सकते हैं।

निजी स्कूल द्वारा छात्रों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप

पीड़ित परिजनों ने सरकार व प्रशासन से की कार्रवाई की मांग

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार राजौंद। राजौंद के पूंडरी मार्ग पर स्थित निजी स्कूल में पढ़ रहे कक्षा तीसरी व दसवीं के विद्यार्थियों के अविभावक ने स्कूल संचालक, प्रिंसिपल, शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता वर्षा पत्नी राजेन्द्र, निवासी गांव सन्तोख मजारा (राजौंद) ने सीएम हरियाणा, उपायुक्त कैथल, एसपी कैथल, जिला शिक्षा अधिकारी कैथल, खंड शिक्षा अधिकारी राजौंद को लिखें पत्र में आरोप लगाया है कि एसपीएन स्कूल प्रबंधन व प्रिंसिपल द्वारा उनके बच्चें के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया और उन्हें पीटा भी जाता है।

शिकायत में उन्होंने बताया कि स्कूल संचालक रमेश कुमार, प्रिंसिपल सुजाता और अध्यापिका सीमरन कौर उनके बच्चों के साथ रंजिश रखतें हैं व बुरी तरह से डंडे से पीटते हैं। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल हिस्सेदार रणबीर सर को पिछले साल 35000 रूपए फीस के रूप में जमा करवाएं थे। बार बार मांगने पर रणवीर सर ने उनको इस रकम की रसीद नहीं दी थी। आरोप लगाया गया कि अब स्कूल वाले फिर से पिछले साल की फीस मांग रहे हैं। उन्होंने दोबारा से फीस जमा करवाने में असमर्थता प्रकट की है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि स्कूल का माहौल खराब हो चुका है। इसलिए वह अपने बच्चों को अब इस स्कूल में नहीं पढाना चाहतीं। उन्होंने स्कूल प्रबंधक से अपने बच्चों का विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र मांगा तो उन्होंने देने से मना कर दिया और कहा कि पहले पिछले पूरे सालों का हिसाब किताब कर, पूरी फीस जमा करवाओ उसके बाद ही विद्यालय त्यागपत्र दिया जाएगा। जबकि वह पिछले वर्षों की पूरी फीस पहले ही जमा करवा चुकी है।

अविभावक वर्षा।

बच्चों की माता वर्षा ने इस संबंध में सरकार व प्रशासन को पत्र लिखकर न्याय मांगा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तत्काल प्रभाव से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। ताकि बच्चों के भविष्य अब और खराब न हो। और समय रहते उसके बच्चों का दाखिला राजौंद के अन्य स्कूलों में करवाया जा सके। इन आरोपों के बारें में स्कूल प्रबंधक रमेश कुमार, रणबीर, स्कूल प्रिंसिपल सुजाता से फोन पर बात की गई तो उन्होंने लगाए गए आरोपी को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने बताया कि जमा करवाई गई फीस की रसीद, वे फीस ले कर तुरंत दे देते हैं। अगर इन्होंने पैसा जमा करवाया है तो वह स्कूल आ कर चेक करवा सकती है बच्चों को स्कूल में पीटने के आरोप के बारे में बताया गया कि उनके स्कूल में डंडे से पीटना की इजाजत नहीं है। यदि किसी अध्यापिका ने बच्चों को थप्पड़ मार दिया होगा तो यह इतनी बड़ी बात नहीं होती। बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए अध्यापकों द्वारा थोड़ा बहुत सख्ती करनी पड़ती है। विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र के बारे में स्कूल प्रबंधक व प्रिंसिपल ने बताया कि अभिभावक वर्ष की ओर से अभी उनके पास विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र बारे में कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने स्कूल प्रबंधक प्रिंसिपल, अध्यापिका पर लगाए गए सभी आरोपो को सिरे से खारिज कर दिया है।

मामले के बारे में खंड शिक्षा अधिकारी बलबीर सिंह कश्यप से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभिभावक वर्ष की ओर से उनके बच्चों पर निजी विद्यालय द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत पर कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी। जांच के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।